उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के आयाम

प्रभात कुमार रॉय

उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव का ऐलान होने के पश्चात राजनीतिक दलों की सरगर्मीयां अत्यंत तीव्र हो गई । उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव का राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम का 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर दूरगामी प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में काँग्रेस के युवराज राहुल गाँधी का स्वयं का भविष्य भी राजनीतिक दांव पर लग गया, क्योंकि राहुल गाँधी ने जाने अनजाने ही उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। राष्ट्रीय काँग्रेस पूरा जोर लगाकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रणक्षेत्र में अपने उखड़े हुए पांवों को फिर से जमाने का प्रयास करने में जुटी गई। राजनीतिक रणक्षेत्र में अपने कमांडर राहुल गाँधी की रणनीति के दमखम पर उतर चुकी कांग्रेस ने अपने खोए हुए वोट बैंक को पुनः हासिल करने के प्रयास में मुसलमानों को साढ़े चार फीसदी आरक्षण प्रदान करने का राजनीतिक निर्णय लिया। धर्म-मजहब के आधार पर प्रदान किए जाने वाला प्रत्येक आरक्षण वस्तुतः असंवैधानिक है, किंतु काँग्रेस ने अपने गंवाए हुए मुस्लिम वोट बैंक को किसी तरह से हस्तगत करने के लिए जोखिम भरा असंवैधानिक दाँव खेल दिया। काँग्रेस के राजनीतिक अवसरवादिता से सरोबार इस दाँव का प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल पर नकारात्मक असर होगा। बहुत जोरशोर से स्वयं को सेकुलर पार्टी घोषित करने वाली कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण का निर्णय यक़ीनन उसे कंलकित कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को काँग्रेस के मुस्लिम आरक्षण दाँव के कारण अपना हिंदू कार्ड चलने का मौका खुदबखुद फ़राहम हो गया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समग्र शैक्षिक और आर्थिक

विकास की प्रबल दरक़ार रही है। मुलसमानों को अगड़ी और पिछडी जातियों में तक़सीम करके और उनको सरकारी नौकरियों में मामूली आरक्षण का झुनझुना पकड़ा कर काँग्रेस अपना राजनीतिक हित साधन करना चाहती है।

विगत कुछ वर्षो से जातिवादी समीकरणों पर टिकी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति को अब सांप्रदायिक आयाम देने का काम काँग्रेस ने अंजाम देने में जुटी है। 90 के दशक के आग़ाज में यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जबकि बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक मोड़ आया और सांप्रदायिक वैमनस्य को परवान चढ़ाकर भाजपा सत्तानशीन हुई तथा कल्यान सिंह मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। कुछ ही वर्ष पश्चात भाजापा के सांप्रदायिक हिंदू कार्ड पर जबरदस्त तौर पर जातिवादी कार्ड हावी हो गया और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी का यादव-मुस्लिम गठजोड़ कार्ड और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के दलित-ब्राहम्ण गठजोड़ कार्ड ने भाजापा और काँग्रेस को प्रदेश की राजनीति में क्रमशः तृतीय और चतुर्थ स्थान पर धकेल दिया।

2007 के विगत चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने निर्णायक शिकस्त देकर और कुल 206 सीटें जीत कर विधान सभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर दिखाया। सुशासन और अपराध मुक्त शासन-प्रशासन की प्रबल उत्कंठा ने बहुजन समाज पार्टी को शानदार विजय का दीदार कराया। जनमानस की उम्मीद पर कायम हुआ मुख्यमंत्री मायावती का एकदलीय शासन भ्रष्टाचार की कुत्सित चपेट में आ गया। भयावह भ्रष्टाचार के इल्जामात में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त महोदय ने अनेक काबीना मंत्रियों के बरखिलाफ आपराधिक रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुशंसा की। मायावती सरकार भारत के इतिहास की प्रथम प्रांतीय सरकार के तौर

पर दर्ज हो गई, जिसने कि अपने 20 से अधिक मंत्रियों को बर्खास्त करने का रिकार्ड कायम किया।

कॉंग्रेस और भाजपा दोनों ने ही मायावती सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामात में घिरे होने का राजनीतिक फायदा लेने की पुरजोर कोशिश की, किंतु क्योंकि कॉंग्रेस की कयादत में यूपीए 2 सरकार भी 2 जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल और कामन वैल्थ गेम्स आदि घोटाले के साथ इतिहास की भ्रष्टतम केंद्रीय हुकूमत बन जाने के कंलक ढोती रही, इसीलिए राहुल गाँधी की मायावती सरकार के विषय में भ्रष्टाचार की बातें एकदम बेअसर साबित हो रही हैं। कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश के कथित विकास को लेकर भी चुनाव रणनीति बनाती रही और बहुत ढोल पीटती रही कि जो भी रुपया केंद्र से उत्तर प्रदेश भेजा गया, उसको मायावती सरकार ने गहन भ्रष्टाचार के चलते खुर्दबुर्द कर दिया। कॉंग्रेस की नाक़ामी ही कही जाएगी कि वह प्रभावहीन नेतृत्व के कारण वह अभी तक न तो मायावती सरकार के भ्रष्टाचार को और ना ही प्रदेश के विकास के प्रश्न को चुनावी मुद्दा बना सकी है। राष्ट्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए आखिरकार राष्ट्रीय कॉंग्रेस कुत्सित सांप्रदायिक राजनीति को अपना हथियार बनाने के लिए विवश हुई।

भाजापा भी उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में नाक़ारा शक्ति सिद्ध हो रही है। कभी एक दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रबल शक्ति रही भाजापा को, कॉंग्रेस के सांप्रदायिक कार्ड का कुछ फायदा हासिल हो सकता है। कॉंग्रेस के पक्ष में यदि मुस्लिम वोटों का धुव्रीकरण होता है, तो यक़ीनन भाजापा के पक्ष में हिंदू वोटो का कुछ ना कुछ धुव्रीकरण होना तो लाजिमी है। बसपा के रुरल हैल्थ मिशन घोटाले में लिप्त पूर्व बसपा मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा को भाजापा में शामिल कर लेने के फैसले ने भाजापा की बहुत फजीहत कराई और पार्टी अंदरुनी कलह को शिकार बनी और भाजपा के भ्रष्ट्राचार विरोधी अन्ना आंदोलन के प्रबल समर्थक होने के

दावे को गंभीर क्षति पंहुची। पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदीदुरप्पा और बेल्लारी स्कैंडल में लिप्त पूर्व मंत्री रेड्डी बंधुओं के कारण भाजापा ने अपनी राजनीतिक छवि पर भयावह भ्रष्ट्राचार के बदनुमा दाग़ लगा चुकी है।

समाजवादी पार्टी अपने समस्त प्रयास के बावजूद अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रखने में नाक़ाम रही है। यादव-मुस्लिम गठजोड़ समीकरण के कमजोर पड़ने के कारणवश और आपराधिक छवि से निरंतर आच्छादित रहने के कारण समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विगत चुनाव जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। विगत विधान सभा चुनाव की अपेक्षा आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव की पहल पर समाजवादी पार्टी ने आपराधिक छवि को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए डी.पी. यादव सरीखे बाहुबली नेता की पार्टी में वापसी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधान सभा का चुनाव संग्राम वस्तुतः सकारात्मक विकास के ज्वलंत राष्ट्रीय प्रश्नों पर होने नहीं जा रहा और इस नकारात्मक राजनीतिक स्थिति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं कथित राष्ट्रीय दल। विशेषकर काँग्रेस और भाजापा इस यथास्थिति के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी हैं जोकि अपनी कथनी और करनी में भारी फर्क़ को बाक़ायदा कायम किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ किसान-मजदूरों की भयंकर बदहाली के प्रश्न हाशिए पर पड़े हैं। 3 करोड़ नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल अनुत्तरित हैं। केवल घृणित सांप्रदायिक और जातिवादी हथकंडों के दमखम से सत्तानशीन हो जाने की जुगाड़ जारी है। वर्तमान चुनाव समीकरण अंततः किसी एक पार्टी के पक्ष में एक स्पष्ट जनादेश के स्थान पर मिलीजुली सरकार के सृजन की ओर इशारा करते नज़र आते हैं।

(पूर्व प्रशासनिक अधिकारी)